मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, गुरुवार 29 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-28, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in





मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का किया शुभारंभ

इंदौर-उज्जैन-भोपाल में 20 लाख रोजगार के अवसर होंगे सृजित

एक सत बुलेटिन, भोपाल



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक, निवेश-अनुकूल, पर्यावरण-संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने, 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित करने तथा 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदौर फ्यूचर सिटी में लगभग 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहर केवल आवासीय क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं। शहरी विकास को आधुनिक अधोसंरचना, जल सुरक्षा, किफायती आवास और बेहतर जीवन गुणवत्ता से जोड़कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में निवेशकों के साथ शहरी विकास एवं अधोसंरचना में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। औद्योगिक कॉरिडोर, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और आधुनिक अधोसंरचना के विकास के साथ सेमीकंडक्टर सहित आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश निवेश, उद्योग, तकनीकी विकास और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संरक्षण एवं उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026 तथा किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 के ड्रॉफ्ट जारी किए। उपचारित जल के पुनः उपयोग का लक्ष्य वर्ष 2037 तक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 2,013 करोड़ रुपये की शहरी अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय समझौते किए गए। विभिन्न एमओयू के माध्यम से औद्योगिक जल के पुनः उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी विकास में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

नीति आयोग की इंदौर इकोनॉमिक रीजन रिपोर्ट (आईईआर) में मालवा-निमाड़ के 8 जिलों के आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2047 तक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें उद्योग, कृषि, पर्यटन और रोजगार से जुड़ी 60 से अधिक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर नगर निगम की सतत विकास रिपोर्ट तथा मध्यप्रदेश एकीकृत भूमि विकास एवं भवन प्रोत्साहन नियम-2026 के प्रारूप को जन परामर्श के लिये प्रस्तुत किया गया।

एमएलसी चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज

'चुनाव बैलेट से हुए, कांग्रेस कितनी सीटें जीती?'

एजेन्सी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि चार बड़े राज्यों में एमएलसी की 28 सीटों पर चुनाव हुए और मतदान बैलेट पेपर यानी मतपत्रों के जरिए कराया गया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं। पीएम मोदी की इस पोस्ट में चुनाव के तरीके और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया है। इन चार राज्यों के चुनाव में अलग-अलग दलों के बीच मुकाबला हुआ है। उपलब्ध नतीजों और रुझानों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी सामने आया है।

उप्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव हुए। फिलहाल तक, पांच सीटों के नतीजे घोषित हुए थे, जिनमें भाजपा ने चार और समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती। भाजपा ने मेरठ शिक्षक, मेरठ स्नातक, बरेली शिक्षक और लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की। बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल की। बाकी सीटों पर मतगणना जारी थी।

गोरखपुर शिक्षक और आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवार आगे थे। वहीं, वाराणसी स्नातक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक और झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे था। मतगणना प्रक्रिया को लेकर भाजपा और सपा ने एक-दूसरे पर आरोप भी लगाए। हालांकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।

बिहार में कांग्रेस को कहां झटका लगा?

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों में से पांच के नतीजे घोषित हुए थे। इन पांच सीटों पर भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), जन सुराज पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक सीट जीती। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद ने पांच बार के भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव को हराया। तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने मौजूदा सीपीआई एमएलसी संजय सिंह को शिकस्त दी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के सुरेश राय ने कांग्रेस नेता और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा को हराया।

पटना स्नातक सीट पर जदयू के नीरज कुमार ने राजद के दिलीप राय को मात दी। सारण सीट पर भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार



ने जीत दर्ज की थी। चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे आने बाकी थे। जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें बाहुबली विधायक अनंत सिंह का समर्थन मिला था। जदयू ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। हार पर अनंत सिंह ने कहा कि जनता जिसे चुनती है, वही जीतता है। वहीं, बात अगर कांग्रेस की करें तो यहां भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली हैं।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव की स्थिति?

कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने विधान परिषद की चारों सीटें जीत लीं। इनमें भाजपा के तीन और जनता दल (सेक्युलर) के एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया था। गठबंधन के उम्मीदवार एपी रंगनाथ ने बंगलूरू शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को हराया। इस सीट पर 81.98 प्रतिशत मतदान हुआ। उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए के शशिल जी नामोशी ने कांग्रेस के शरणप्पा मत्तूर को शिकस्त दी।

महाराष्ट्र में विधान परिषद की पांच सीटों के लिए महायुति और महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार मैदान में थे। कुल 182 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इन सीटों में तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। उपलब्ध रुझानों के मुताबिक, दो सीटों पर भाजपा, एक पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दो पर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे थी। पांचों सीटों के अंतिम नतीजे अभी घोषित नहीं हुए थे। इस तरह चार राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी का सवाल सामने आया, लेकिन उनकी पोस्ट में पार्टी की कुल जीती हुई सीटों का आंकड़ा नहीं दिया गया।

'ईवीएम हो या मतपत्र, नतीजा एक जैसा': प्रह्लाद जोशी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जोशी ने तंज कसते हुए कहा, मत पत्र हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), कांग्रेस पार्टी का नतीजा एक जैसा ही रहता है। उन्होंने विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के एक भी सीट नहीं जीतने पर यह टिप्पणी की। वर्ष 2026 के विधान परिषद चुनावों के नतीजे चार राज्यों की 28 सीटों पर घोषित किए गए हैं। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं।



विधान परिषद के मौजूदा सदस्य भी अपनी सीटें नहीं बचा सके

प्रह्लाद जोशी ने कहा, कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाती है। वह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल करती है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में नहीं आते, तो वह व्यवस्था को दोष देने लगती है। कांग्रेस शासित कर्नाटक का खास तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि विधान परिषद के मौजूदा सदस्य भी अपनी सीटें नहीं बचा सके। उन्होंने कहा, कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती है। वह कथित गड़बड़ियों को लेकर भी शिकायत करती है। लेकिन जब मतपेटी के जरिये चुनाव हुए, तब भी पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी। उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जोशी ने दावा किया कि चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

चार राज्यों में किन सीटों पर हुए चुनाव?

- विधान परिषद के चुनाव चार राज्यों में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल 28 सीटों पर हुए थे।
- उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे।
- बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव हुए। इनमें चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र थे।
- महाराष्ट्र में विधान परिषद की पांच सीटों पर चुनाव हुए। इनमें तीन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे।
- कर्नाटक में कांग्रेस चारों निर्वाचन क्षेत्रों में हार गई।

एमपी से राज्यसभा जाएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

एक सत बुलेटिन, भोपाल

भाजपा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 28 अक्टूबर को उनके नाम की घोषणा की। पुरी केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं।



यह सीट केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर 12 नवंबर को मतदान होगा। इसी दिन शाम 5 बजे काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए सामान्य स्थिति में 116 मतों का कोटा है। हालांकि, कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऐसे में 229 विधायकों के आधार पर चुनावी गणित तय होगा और जीत का कोटा निर्धारित नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। बीना विधायक निर्मला सप्रे की स्थिति भी अहम है। वे खुद को कांग्रेस में बताती हैं, लेकिन भाजपा के कार्यक्रमों में भी नजर आती रही हैं। दलबदल से जुड़े मामले के कारण उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

स्पेन में हाई स्पीड ट्रेनें टकराईं, 64 की मौत

एजेन्सी, मैड्रिड



स्पेन के टोलेडो प्रांत में बुधवार को दो हाई स्पीड ट्रेनें टकरा गईं। डीडी न्यूज के मुताबिक, हादसे में 64 लोगों की मौत हो गई, जबकि 179 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव के लिए इमरजेंसी और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंचीं। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक, हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे मोरा और ओरगाज कस्बों के बीच हुआ। एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

हादसे के बाद राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी अंदालूसिया क्षेत्र से जोड़ने वाली रेल लाइन बंद कर दी गई। दोनों ट्रेनें सरकारी कंपनी रेनफे और निजी कंपनी इर्यो की थीं। इन ट्रेनों की रफ्तार आमतौर पर 200 किमी/घंटे से ज्यादा होती है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने कहा कि इस हादसे की खबर सुनकर वे सदमे में हैं। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और हादसे में प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं।

टोलेडो के पास उर्दा शहर के मेयर मैनुअल गालान ने बताया कि बचाव दल ने उनसे घायलों के इलाज और देखभाल के लिए एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार रखने को कहा है।

केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा

महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा, नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू

एजेन्सी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी को औपचारिक मंजूरी दे दी है। बढ़ती महंगाई के बीच लिए गए इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी गई।

केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और राहत के मद में कुल 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डीए और डीआर बढ़ने से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।



कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसले के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगी। कर्मचारियों के जीवन यापन की बढ़ती लागत असर को संतुलित करने के मकसद से सरकार समय-समय पर इस भत्ते में बदलाव करती है। बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किए गए इस तीन प्रतिशत के इजाफे के लिए सरकार ने कुल 10,016 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया है।

कैबिनेट की बैठक में और किन योजनाओं को मंजूरी मिली?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण

कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीमः देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीमः खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए 1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजनाः ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से 7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है।

महंगाई भत्ता/राहतः कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए 10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत देने वाला कदम है। ?10,016 करोड़ के इस वित्तीय प्रावधान के साथ-साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मंजूर किया गया ?29,267 करोड़ का कुल पैकेज से देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में बताता है।

तीन फीसदी के इस नए इजाफे से

वेतन और पेंशन में वृद्धिः केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मासिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज होगी।

आर्थिक संबलः महंगाई के दबाव के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिवारिक बजट को मजबूती देगी

वित्तीय प्रभाव का विवरण

कुल वित्तीय परिव्ययः डीए और डीआर के मद में 10,016 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

बाजार में लिक्विडिटीः इस फंड के जारी होने से बाजार में कंजप्शन और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सकारात्मक असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।

महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाएंगी मिशन, डॉ. पूर्णिमा तिवारी बनीं मिसेज यूनिवर्स एंबेसडर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट के मंच पर खड़ी होकर देश का प्रतिनिधित्व करूंगी। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा करना रहा है। लेकिन जब समाज में महिलाओं को इनफर्टिलिटी (निःसंतानता) जैसी समस्याओं से जूझते और इसके कारण मानसिक व सामाजिक दबाव झेलते देखा, तो महसूस हुआ कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कुछ अलग करना होगा। इसी सोच ने मुझे एक नई राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह बात भोपाल की डॉ. पूर्णिमा तिवारी ने बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। डॉ. पूर्णिमा ने कहा कि श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स एंबेसडर का खिताब हासिल करना मेरे लिए सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए काम करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है।

85 किलो वजन से शुरू हुआ सफर

पूर्णिमा ने बताया कि करीब एक साल पहले मेरा वजन 85 किलो था। तभी मैंने तय किया कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना है। यह फैसला आसान नहीं था। मैंने सबसे पहले अपने पति से बात की। उन्होंने न केवल मेरी बात सुनी, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

पिछले दस महीनों में उनका सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत रहा। फिटनेस के लिए सुबह पांच बजे उठने से लेकर रात 11 बजे तक ट्रेडमिल पर मेहनत करने तक, मैंने अपनी दिनचर्या में बड़े बदलाव किए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। शारीरिक मेहनत, अनुशासन और





खुद को लगातार बेहतर बनाने की चुनौती आसान नहीं थी। लेकिन पति और परिवार के सहयोग ने मुझे हार नहीं मानने दी। इस सफर ने सिखाया कि किसी भी उम्र में अपने लिए नया लक्ष्य तय किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर मेहनत और अपनों के विश्वास की।

मेरी नेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर ज्योति परिहार थीं, जो आईवीएफ विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने आईवीएफ की अवधारणा से प्रेरित होकर टेस्ट-ट्यूब बेबी की थीम पर मेरी पोशाक तैयार की। यह मेरे लिए खास अनुभव था, क्योंकि इसने मेरे पेशे और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को भी मंच पर अभिव्यक्त किया। मिसेज यूनिवर्स एंबेसडर का खिताब मिलने के बाद मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर मैदानी स्तर पर काम करना चाहती हूं। मेरा मानना है कि जब महिलाएं स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर होंगी, तभी समाज वास्तव में आगे बढ़ेगा। मैं चाहती हूं कि मेरी यात्रा दूसरी महिलाओं को यह विश्वास दिलाए कि परिवार का सहयोग, आत्मविश्वास और मेहनत साथ हों, तो जीवन में नई शुरुआत करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 96वीं रैंक हासिल करना मेरे जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और नियमित निगरानी पर दिया जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाभाव और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ दें बांड डॉक्टर्स : उप मुख्यमंत्री

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहडोल संभाग के शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर जिले में नवपदस्थ बांड डॉक्टर्स से संवाद किया। उन्होंने चिकित्सकों को ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाभाव, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि नवपदस्थ चिकित्सकों को स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधाओं, जांच सेवाओं, एंबुलेंस एवं रेफरल व्यवस्था तथा शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं का व्यवस्थित ओरिएंटेशन दिया जाए। चिकित्सक एनीमिया मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत एवं गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग जैसे अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आशा, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, प्रसवपूर्व जांच और सुरक्षित प्रसव



सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि बीएमओ सप्ताह में एक बार तथा सीएमएचओ माह में एक बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और कमियों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का प्रभावी उपयोग बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बांड डॉक्टर्स का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और आमजन का विश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। सभी चिकित्सक पूरी प्रतिबद्धता और टीम भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। वीसी में शहडोल संभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं नवपदस्थ बांड डॉक्टर्स शामिल थे।

बांड डॉक्टर्स समर्पण के साथ दें स्वास्थ्य सेवाएँ: राजेंद्र शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बांडेड चिकित्सकों से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा, सेवाभाव और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है और इसमें युवा डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवाभाव पर जोर : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक बड़ा अवसर है। स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण : दूरस्थ इलाकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बांड डॉक्टर्स की तैनाती एक अहम कदम है। चिकित्सकों को प्रोत्साहन : सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे डॉक्टरों के लिए बेहतर माहौल और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत बनाएं, निर्बाध संचालन सुनिश्चित करें : मंत्री कुशवाहा



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्री श्री कुशवाहा ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत बनाने और उनका निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रों के संचालन में आ रही कठिनाइयों का समाधान कर उनकी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। मंत्री श्री कुशवाहा ने डीडीआरसी में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा जिलों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 51 जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 और वर्ष 2025-26 में 37 केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। केंद्रों के मानव संसाधन, कार्यों और गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने सभी संस्थानों में सतत् निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिये। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्री के.जी. तिवारी ने बताया कि प्रदेश में संचालित 89 वृद्धाश्रमों में 2,423 वरिष्ठजन निवासरत हैं। 22 जिलों में 31 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का हुआ आयोजन





■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

जिला रोजगार कार्यालय, भोपाल द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न कंपनियों ने सहभागिता कर जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए।रोजगार मेले में कुल 16 कंपनियों ने भाग लिया।

मेले के अंतर्गत कुल 160 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 107 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके कौशल एवं क्षमता के अनुरूप अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय रेल देश भर में 1,265 स्टेशन मास्टरों की भर्ती करेगा

रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे में 49 और पश्चिम रेलवे में 13 पद, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भारतीय रेल ने केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 08/2026 के तहत स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के माध्यम से देशभर में कुल 1,265 स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति की जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से भारतीय रेल अपने परिचालन कार्यबल को मजबूत करने के साथ-साथ योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। रेलवे बोर्ड द्वारा स्टेशन मास्टर के पदों के लिए अलग से केंद्रीकृत रोजगार सूचना जारी की गई है, जिससे उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, परीक्षा पद्धति और रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आरआरबी एवं रेलवे जोनवार रिक्तियों के



विवरण के अनुसार, आरआरबी भोपाल के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे में स्टेशन मास्टर के कुल 49 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग के 21, अनुसूचित जाति के 8, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों के लिए 5 पद दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार, आरआरबी भोपाल के अंतर्गत पश्चिम रेलवे में स्टेशन मास्टर के कुल 13 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित वर्ग के 5, अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 पद शामिल है। इस प्रकार, उपलब्ध तालिका के अनुसार भोपाल से संबंधित इन दोनों प्रविष्टियों में स्टेशन मास्टर के कुल 62 पद दर्शाए गए हैं। सीईएन संख्या 08/2026 के अंतर्गत देशभर के विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों और रेलवे जोनों में कुल 1,265 पदों पर भर्ती की जाएगी। जारी विवरण के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में रिक्तियों का वितरण किया गया है, जिससे पात्र उम्मीदवार अपनी योग्यता एवं संबंधित भर्ती बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना में दी गई शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण संबंधी प्रावधानों, परीक्षा प्रक्रिया और अन्य आवश्यक शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें।

अधिकारी जनसमस्याओं का करें त्वरित निराकरण, समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक

संभाग में किसानों को आवश्यकता के अनुसार मिलें खाद बीज एवं अन्य कृषि अनुदानः संभागायुक्त

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि रबी 2026- 27 के लिए प्रदेश के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद, बीज एवं अन्य कृषि अनुदान सुगमता से प्राप्त हों, इसके लिए कृषि, सहकारिता और अन्य सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। संभाग में खाद बीज आदि की पर्याप्त उपलब्धता है। किसानों को फसलों के विविधीकरण, उर्वरक के संतुलित उपयोग, प्रमाणित बीजों के प्रयोग, नराली न जलाने और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। इस वर्ष किसानों को फसलों की जल्दी बुवाई के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे वे वर्तमान में मिट्टी में उपलब्ध नमी का उपयोग कर सकें। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व श्रीमती भारती देवी मिश्रा सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति हो। बिजली की अनावश्यक कटौती ना की जाए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों में जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। संभागायुक्त श्री



शर्मा ने निर्देश दिए कि अधिकारी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत न केवल शिविर में जन समस्याओं का समाधान करें अपितु उस केन्द्र की शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय को समय से भिजवाएं और परख पोर्टल पर भी अपलोड करें। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि जन विश्वास शिविर में प्राप्त शिकायतों के साथ ही सी.एम. हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी प्रकरणों का भी निराकरण करें। सी.एम. हेल्पलाइन का कोई भी प्रकरण 50 दिन से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। संभागायुक्त श्री शर्मा ने कहा कि इस बार शासन द्वारा किसानों को खाद्य वितरण व्यवस्था को अत्यंत सुगम बनाया गया है। किसान घर बैठे ही खाद के लिए व्हाट्सएप से टोकन जनरेट कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। फसल बोने वाले प्रत्येक किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाएगा। श्री शर्मा ने अधिकारियों को खाद्य वितरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि किसान को खाद्य प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। संभागायुक्त श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों में नरवाई जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए किसानों को समझाइश दी जाए तथा हार्वेस्टर के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए। हर हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) लगा होना चाहिए, इससे नरवाई मिट्टी में मिल जाती है। किसानों को फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करें।

न्यूज ब्रीफ

शराब के लिए दो हजार रुपये मांगे, नहीं देने पर चाकू मारा

जबलपुर। शराब पीने के लिए दो हजार रुपये देने से मना करने पर तीन बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से कई वार किए, फिर गोली मार दी।वारदात में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लार्डगंज पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार, सुपर मार्केट गंजीपुरा निवासी तरुण मिरगे उर्फ अनुपम (26) सोमवार रात अपने दोस्त आशु साहू के साथ बड़ा फुहारा से समोसे लेकर मोपेड से लौट रहा था।दोनों साहू मोहल्ला पहुंचे, तभी सत्या सिंह राजपूत, सत्यम साहू और वीरू संग्राम ने उन्हें रोक लिया। तीनों ने शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे। तरुण के मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।आरोप है कि वीरू संग्राम ने तरुण को पकड़ लिया, जबकि सत्यम साहू ने उस पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद सत्या सिंह राजपूत ने गोली चला दी, जो तरुण के पैर में लगी। वारदात के बाद तीनों आरोपित मौके से भाग निकले।

घुमक्कड़ों के लिए एसी बसों से पर्यटन स्थलों का सफर आसान

जबलपुर। जबलपुर में पर्यटन स्थलों तक पहुंचना और घूमने के बाद शहर लौटना अब पहले की तुलना में आसान हो रहा है। नगर निगम की एसी बसें सार्वजनिक परिवहन के सुविधाजनक विकल्प के रूप में लोगों के काम आ रही हैं।इन बसों से पर्यटक शहर के विभिन्न हिस्सों से आवागमन कर रहे हैं। ठंड के मौसम में भी एसी बसों में सफर आरामदायक बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने जाने वाले लोगों को सहूलियत खासकर परिवार के साथ घूमने जाने वाले लोगों को इससे सहूलियत मिल रही है। शाम तक पर्यटन स्थलों पर समय बिताने के बाद शहर लौटने के लिए सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलने से निजी वाहन की अनिवार्यता भी कम हुई है।

नवंबर अंत तक पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी कराने हाईकोर्ट के निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विशाल धगट की एकलपीठ ने बालाघाट जिले में व्याख्याता पद पर पदोन्नति से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए अपने महत्वपूर्ण निर्देश में सक्षम प्राधिकारी को नवंबर 2026 के अंत तक समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी करने और नियमानुसार पदोन्नति पर आदेश पारित करने कहा हैं।बालाघाट के देवेंद्र पटले सहित अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि बालाघाट जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप अधिकारियों की गलती के कारण याचिकाकर्ताओं और उनके समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अवसर नहीं मिला। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्रुटि सुधारने और रिव्यू डीपीसी आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता गिरीश प्रकाश केकरे ने बताया कि मामले में जवाब या शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन टेलीफोन पर मिली जानकारी के अनुसार संभावित त्रुटि सुधारने के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया नवंबर 2026 में पूरी किए जाने की संभावना जताई गई। न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद सक्षम प्राधिकारी को नवंबर के अंत तक रिव्यू डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर पदोन्नति के संबंध में नियमानुसार आदेश पारित करने के निर्देश दिए।

लक्ष्मीपुर बस्ती के 250 परिवारों को हटाने के मामले में फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जबलपुर के एमआर-फोर रोड से लगी लक्ष्मीपुर बस्ती में रह रहे लगभग 200 से 250 परिवारों को हटाने के मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जबलपुर नगर निगम, जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), केसरवानी शिक्षा समिति और बस्ती के रहवासियों का पक्ष प्रस्तुत किया गया। बस्ती के रहवासियों की ओर से हस्तक्षेपकर्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर और अधिवक्ता रवींद्र कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने एकलपीठ के समक्ष दलील दी कि उक्त बस्ती में पट्टाधारी परिवारों सहित लगभग 200 से 250 परिवार निवास कर रहे हैं।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आयुक्त से की शिकायत

समयसीमा खत्म, फिर भी शहर की सड़कों से नहीं हटे यूनिपोल



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर की मुख्य सड़कों पर समयसीमा समाप्त होने के बावजूद यूनिपोल लगे रहने और होर्डिंग संचालकों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर यूनिपोल और होर्डिंग के मामले में आउटडोर मीडिया नियम-2017 के तहत जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मंच ने आरोप लगाया है कि नियमों का पालन नहीं होने से नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को की गई शिकायत में बताया गया है कि शहर में यूनिपोल लगाने की अनुमति कई एजेंसियों को वर्ष 2014-15 में दी गई थी। इनकी दस साल की समयसीमा वर्ष 2024-25 में समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद शहर की प्रमुख सड़कों पर यूनिपोल लगे हुए हैं और उन्हें हटाने के लिए नगर निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायत में ग्वालियर की होर्डिंग एजेंसी का भी उल्लेख किया गया है। मंच के अनुसार, एजेंसी को केवल तीन साल के लिए यूनिपोल लगाने की अनुमति मिली थी, लेकिन समयसीमा समाप्त होने के बाद भी यूनिपोल नहीं हटाए गए। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी पिछले छह वर्षों से एजेंसी को उपकृत करते आ रहे हैं।

डिस्प्ले बोर्ड लगाकर वसूला जा रहा किराया.....

मंच ने शिकायत में कहा है कि यूनिपोल पर दोनों तरफ डिस्प्ले बोर्ड लगाकर होर्डिंग संचालक नगर निगम को कथित तौर पर बिना साइड किराया और टैक्स दे रहे हैं। टैक्स जमा कराने के नाम पर होर्डिंग संचालकों को मांग पत्र भेजकर औपचारिकता पूरी की जा रही है। मंच ने इसे आउटडोर मीडिया नियम-2017 का उल्लंघन बताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में सर्वोच्च न्यायालय के बजाय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। मंच के अनुसार, डब्ल्यूपी क्रमांक 26109/2024 में 18 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि यूनिपोल और होर्डिंग के संबंध में आउटडोर मीडिया नियम-2017 के तहत कोई शिकायत होने पर उसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। मंच ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को शिकायत भेजकर शहर में लगे यूनिपोल और होर्डिंग की अनुमति, समयसीमा, किराया और टैक्स संबंधी रिकॉर्ड की जांच कराने तथा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

अंडरवियर पहनकर बिस्तर पर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारी, जज बोले- क्यों ना की जाए आप पर कार्रवाई

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



हाई कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अनुचित पहनावे और आचरण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश न्यायालय ने पूछा है कि उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। साथ ही राज्य शासन को संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई कर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने यह आदेश जीएसबी कंस्ट्रक्शन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। आदेश के अनुसार, न्यायालय ने नौ अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। ऐसा नहीं होने पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिस्तर पर उपस्थित हुए। उस समय वह शर्ट के बटन बंद कर रहे थे और अंडरवियर पहने हुए थे। न्यायालय ने उनके इस आचरण को न्यायालय की गरिमा के प्रतिकूल और अवमाननापूर्ण माना। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने तुरंत टिप्पणी की कि इस प्रकार का आचरण न्यायपालिका के सम्मान के खिलाफ है। अदालत ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए पूछा कि उनके इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए उन पर अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। सुनवाई के दौरान मौजूद अन्य अधिवक्ताओं और अधिकारियों में भी इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। उच्च न्यायालय ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि वर्चुअलाइजेशन के दौर में भी अदालती प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। अदालत ने अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में ओपन काउंसलिंग से होगी प्राचार्यों की पदस्थापना

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रभारी प्राचार्यों की पदस्थापना और वरिष्ठता विवाद पर संबंधित प्राध्यापकों के लिए कॉमन ओपन काउंसलिंग आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य शासन की रिट अपीलों का निराकरण करते हुए पदस्थापना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित की। प्रभारी प्राचार्य के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी इस मामले में प्रोफेसर डॉ. यशवंत कुमार मिश्रा ने डॉ. वस्तोष्पति शास्त्री की प्रभारी प्राचार्य के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी थी। कॉमन काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे संबंधित महाविद्यालय रतलाम स्थित शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। चार सितंबर 2025 को एकलपीठ ने अधिक विकल्प देने अथवा कॉमन काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे। इसके विरुद्ध राज्य शासन सहित संबंधित पक्षों ने रिट अपीलें दायर कीं। अपने वर्तमान महाविद्यालय में बने रह सकते हैं युगलपीठ के निर्देशानुसार, प्राचार्य अथवा प्रभारी प्राचार्य बनने के इच्छुक संबंधित प्राध्यापकों के लिए ओपन काउंसलिंग होगी। पसंद का महाविद्यालय नहीं मिलने पर वे दो अन्य शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे अथवा अपने वर्तमान महाविद्यालय में बने रह सकते हैं।

ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़ गए 95 हजार रुपये

ड्रायफ्रूट सप्लाई के मुनाफे से लेकर निवेश पर रिटर्न तक का लालच, जबलपुर में ठगी का जाल

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



स्मार्ट सिटी में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ताज़ा मामलों में ठगों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में तीन लोगों को अपना शिकार बनाया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कराने, सूखे मेवों की सप्लाई और मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों के बैंक खातों से कुल दो लाख नौ हजार रुपये की चपत लगाई गई है। पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर संजीवनी नगर, विजय नगर और अधारताल थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, साईं कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय सुधांशु श्रीवास्तव पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। बीते 16 अक्टूबर को जब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे थे, तब उनकी नजर 'टीवी गार्डन' ऐप के एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन देखकर उन्होंने उस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। ऐप डाउनलोड होने के तुरंत बाद उनकी स्क्रीन पर 'हिंदी प्लस' नाम का एक अन्य लॉन्चर डाउनलोड करने का विकल्प फ्लैश हुआ। जैसे ही उन्होंने उस विकल्प पर क्लिक कर लॉन्चर डाउनलोड किया, उनके बैंक खाते से एक झटके में 95 हजार रुपये कट गए। खाते से अचानक बड़ी रकम निकलने की जानकारी मिलते ही उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया।

पश्चिम मध्य रेल से होकर पुणे-दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन 09-09 ट्रिप संचालित होगी

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



त्योहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गाड़ी संख्या 01441/01442 पुणे-दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदनमहल, कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों पर ठहराव लेकर संचालित होगी। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है। गाड़ी संख्या 01441 पुणे-दानापुर स्पेशल ट्रेन (रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार) दिनांक 01 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक 09 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन पुणे स्टेशन से रात 19:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी स्टेशन पर 11:15 बजे, पिपरिया 12:24 बजे, नरसिंहपुर 13:30 बजे, मदनमहल 15:30 बजे, कटनी 16:50 बजे, मैहर 17:43 बजे एवं सतना स्टेशन पर 18:50 बजे पहुंचेगी। इसके बाद तीसरे दिन सुबह 07:00 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01442 दानापुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन (मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एवं सोमवार) दिनांक 03 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक 09 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन दानापुर स्टेशन से सुबह 08:30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन पश्चिम मध्य रेल के सतना स्टेशन पर 18:25 बजे, मैहर 18:50 बजे, कटनी 19:40 बजे, मदनमहल 22:00 बजे एवं नरसिंहपुर 23:05 बजे पहुंचेगी। अगले दिन पिपरिया स्टेशन पर 00:18 बजे तथा इटारसी स्टेशन पर 02:10 बजे पहुंचेगी। इसके बाद हड़पसर स्टेशन पर 17:35 बजे पहुंचेगी।

तिरुवनंतपुरम उत्तर-हज़रत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) स्पेशल ट्रेन का 03-03 ट्रिप संचालन

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



त्योहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 06073/06074 तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली)-हज़रत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का दोनों दिशाओं में 03-03 ट्रिप संचालन किया जा रहा है। इस स्पेशल ट्रेन को पश्चिम मध्य रेल के इटारसी एवं रानी कमलापति स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। गाड़ी संख्या 06073 तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली)-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन दिनांक 2, 9 एवं 16 नवंबर 2026 को प्रत्येक सोमवार तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) स्टेशन से दोपहर 14:00 बजे प्रस्थान करेगी। मार्ग में यह ट्रेन तीसरे दिन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी स्टेशन पर 06:10 बजे एवं रानी कमलापति स्टेशन पर 07:45 बजे पहुंचेगी। इसके बाद उसी दिन बुधवार को रात्रि 23:50 बजे हज़रत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 06074 हज़रत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन दिनांक 5, 12 एवं 19 नवंबर 2026 को प्रत्येक गुरुवार हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से प्रातः 05:45 बजे प्रस्थान करेगी। मार्ग में यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के रानी कमलापति स्टेशन पर रात 20:40 बजे एवं इटारसी स्टेशन पर रात 22:35 बजे पहुंचेगी। इसके बाद तीसरे दिन शनिवार को सायं 16:30 बजे तिरुवनंतपुरम उत्तर (कोच्चुवेली) पहुंचेगी। कोच संरचनाः इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें 02 जनरेटरकार, 10 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी एवं 06 वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के कोच शामिल हैं। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वर्कला शिवगिरी, कोल्लम जंक्शन, कायमकुलम जंक्शन, मावेलिक्करा, चेंगन्नूर, तिरुवल्ला, चन्नानाशेरी, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी जंक्शन, ग्वालियर जंक्शन, आगरा छावनी एवं मथुरा जंक्शन स्टेशनों पर ठहरेगी।

श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 30 अक्टूबर से, पूज्य विपिन बिहारी जी महाराज करेंगे कथा

जालम सिंह पटेल बोले-यह किसी एक परिवार का नहीं, पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक आयोजन

एक सत बुलेटिन, गोटेगांव



नगर के लाठगांव बायपास चौराहे स्थित मणिनागेंद्र सिंह सैनिक स्कूल परिसर में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा में पूज्य कथावाचक एवं गौ पीठाधीश्वर पं. विपिन बिहारी जी महाराज के श्रीमुख से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भागवत कथा की अमृतमयी वाणी का श्रवण कराया जाएगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां की जा रही हैं। दिवंगत माताजी और मोनू भैया की स्मृति में आयोजन मंगलवार, 28 अक्टूबर को कथा स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्यप्रदेश शासन के पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ उनकी पूज्य माताजी स्वर्गीय यशोदा बाई पटेल एवं उनके प्रिय पुत्र स्वर्गीय मणिनागेंद्र सिंह पटेल (मोनू भैया) की पावन स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि, सद्भावना और सर्वकल्याण की कामना करना है। 'हर श्रद्धालु स्वयं को यजमान मानकर कथा में शामिल हो' जालम सिंह पटेल ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ किसी एक परिवार का निजी कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का आध्यात्मिक एवं सामाजिक आयोजन है। यह यज्ञ पूर्वजों की आत्मशांति, क्षेत्र में शांति-सद्भाव और जनकल्याण की भावना को समर्पित है। इसमें संपूर्ण श्रीधाम क्षेत्र की सहभागिता और सभी के आशीर्वाद की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि उनके पूज्य पिताजी मुलाम सिंह पटेल मुख्य यजमान के रूप में आयोजन में उपस्थित रहेंगे, लेकिन इस कथा की मूल भावना सामूहिक श्रद्धा और सहभागिता है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु स्वयं को यजमान माने। यह किसी एक व्यक्ति या परिवार का यज्ञ नहीं, बल्कि सभी की आस्था और समर्पण का महायज्ञ है। पूर्व राज्यमंत्री पटेल ने पूज्य शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, साधु-संतों, महात्माओं, विप्रजनों, सनातन धर्मावलंबियों, जनप्रतिनिधियों, मातृशक्ति और समस्त धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से कथा में शामिल होकर धर्मलाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी श्रद्धालु तक व्यक्तिगत आमंत्रण पत्र नहीं पहुंच पाया हो, तो वे इस सार्वजनिक निवेदन को ही आत्मीय आमंत्रण मानकर अपने परिवार सहित कथा में शामिल हों।

संपादकीय

भारत में संकटों का दौर

राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बम गिराएंगे या नहीं अथवा मध्यावधि चुनाव के बाद हमलों का नया दौर शुरू करेंगे, यह वह ही जानते हैं। कुछ भी कहना अनिश्चित है, क्योंकि ट्रंप भी मानसिक तौर पर अस्थिर राजनेता हैं। यह राष्ट्रपति ट्रंप का दिमागी फितूर, अहंकार और उनकी सनक है, जिसके मुताबिक वह फैसले लेते हैं। यह अमरीकी जनता के लिए भी महंगाई, बेरोजगारी, मंदी का दौर है, यूरोपीय देश जबरदस्त विरोध-प्रदर्शनों से धू-धू जल रहे हैं, दुनिया के अधिकतर देश सप्लाई चेन के टूटने के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। यदि ईरान युद्ध का नया दौर शुरू हुआ, तो वह पहले से अधिक भयावह और विध्वंसक होगा, लिहाजा कच्चे तेल के दाम 150-200 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकते हैं, ऐसे अर्थशास्त्रियों और अनुभवी रक्षा विशेषज्ञों के आकलन हैं। इंडियन बॉस्केट में कच्चा तेल करीब 120 डॉलर प्रति बैरल पड़ रहा है, जबकि बाजार के दाम 115 डॉलर को छू चुके हैं। भारत के लिए यह कई संकटों का दौर है। बेशक युद्ध बुनियादी कारण है, लेकिन कुदरत भी हमसे नाराज है। हमारी मुद्रा रुपए का लगातार अवमूल्यन जारी है। विदेशी निवेश कम मिल रहा है। जिन विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार में निवेश किए थे, उन्होंने अक्तूबर माह में ही 48056 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। जनवरी से अब तक करीब 3.08 लाख करोड़ रुपए के निवेश निकाले जा चुके हैं। कच्चे तेल की कीमतें महंगी होने के कारण आयात बिल 11.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ कर करीब 20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। यह भुगतान डॉलर में करना पड़ता है, लिहाजा विदेशी मुद्रा भंडार भी प्रभावित होगा। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण तेल के दाम बढ? से भारत को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारत सरकार ने जो कर्ज ले रखा है, उस पर ब्याज ही 14 लाख करोड़ रुपए है। आखिर यह पैसा कहां से आएगा? ऐसे देश में कोई विदेशी निवेशक बड़ा निवेश क्यों करेगा? भारत सरकार के सूत्रधार यह स्वीकार करें अथवा न करें, हकीकत की एक बानगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पेश की है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे इस बार रबी की फसल न बोएं, क्योंकि वह पानी मुहैया नहीं करा सकते। पानी की घोर किल्लत है।

पानी के भीषण संकट के कारण तेलंगाना के किसान 55 लाख हेक्टेयर में से 13 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करना पहले ही छोड़ चुके हैं। किसानों ने अपना धंधा ही छोड़ दिया है और शहर में मजदूर बन रहे हैं। अब ई-100, अर्थात 100 फीसदी एथेनॉल वाली, कारों की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन इस पर न तो अर्थशास्त्री और न ही विपक्ष आवाज उठा रहे हैं कि एथेनॉल और डाटा केंद्रों में कितना पानी बहाया जा रहा है? भारत में भयंकर सूखे के ऐसे हालात हैं कि महाराष्ट्र में 358 में से 305 और कर्नाटक में 240 में से 226 तालुका सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कर्नाटक में 150 सालों का सूखे का सबसे भीषण संकट सामने है। यह कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। महाराष्ट्र देश की नंबर वन और कर्नाटक तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं। सरकारें खाद्य-संकट से कैसे बचाएंगी? इसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा, जिस पर देश का 42 फीसदी कार्यबल आश्रित है। भारत जो कच्चा तेल और गैस खाड़ी देशों से लेता था, अब अमरीका से अंगोला जैसे देशों के सहारे है। बीते एक साल में अमरीका से एलएनजी का आयात 10 फीसदी से बढ़ कर 67 फीसदी पर पहुंच गया है। अमरीका से तेल-गैस मंगवाना 20 फीसदी महंगा पड़ रहा है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, हालात ये हैं कि महंगाई की दर 6.45 फीसदी तक बढ़ सकती है। खाद्य महंगाई दर अभी 8 फीसदी से अधिक है। दिसंबर में रेपो रेट भी 5.5 से बढ़ कर 6 फीसदी हो सकता है। मार उस आम आदमी पर ही पड़ेगी, जो किस्तों में जिंदगी जी रहा है। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इससे और महंगे तेल के कारण हमारा चालू खाता घाटा 2 फीसदी तक बढ़ सकता है। यह दौर सरकार की चुप्पी का नहीं है। आसार ऐसे उभर रहे हैं कि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो देश में कमोबेश यूरोप जैसे हालात बन सकते हैं! पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से हाहाकार मचा हुआ है। इससे भारत भी प्रभावित हुआ है। तेल की खरीद के लिए देश को लाखों डालर खर्च करने पड़ रहे हैं।

पटेल के सपनों का भारत और हमारी जिम्मेदारी

डा. मनोज डोगरा

> **जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक तनाव, क्षेत्रीय असहिष्णुता, अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं। छोटी-छोटी बातों पर आपसी मतभेदों को दुश्मनी में बदल देना राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि देश की एकता केवल सरकारों या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।**

देश की अखंडता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करवाती है। भारत विविधताओं का देश है। यहां अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और रीति-रिवाजों के लोग एक साथ रहते हैं। हमारी यही विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोकर रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती भी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। इस ऐतिहासिक कार्य को जिस महान व्यक्तित्व ने अदम्य साहस, दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ पूरा किया, वे थे भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

लौह पुरुष का अद्वितीय योगदान : सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन, साहस और राष्ट्रसेवा की प्रेरणादायक मिसाल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें ह्यसरदारह्ण की उपाधि मिली, जो आगे चलकर उनके नाम का अभिन्न हिस्सा बन गई। पटेल केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक, दृढ़ निर्णय लेने वाले नेता और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रनायक भी थे। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, प्रशासनिक अव्यवस्था और रियासतों के भविष्य जैसी गंभीर समस्याएं थीं। ऐसे कठिन समय में उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया।

रियासतों का एकीकरण : आधुनिक भारत की नींव : 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस समय देश का राजनीतिक एकीकरण पूरा नहीं हुआ था। ब्रिटिश शासन के अंत के साथ सैकड़ों देशी रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा अपने भविष्य का निर्णय करने का प्रश्न था। इन रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करना अत्यंत जटिल कार्य था। सरदार पटेल ने वीपी मेनन जैसे कुशल प्रशासनिक सहयोगियों के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने संवाद, कूटनीति, समझदारी और आवश्यक दृढ़ता के माध्यम से अधिकांश रियासतों को भारत में शामिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे मामलों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की प्रक्रिया की अपनी अलग परिस्थितियां थीं, जिनमें तत्कालीन शासक और अन्य राष्ट्रीय नेतृत्व की भी भूमिका रही। यह कार्य केवल राजनीतिक सीमाओं को जोड? तक सीमित नहीं था। इसका वास्तविक उद्देश्य भारत की एकता, सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। यदि उस समय रियासतों का एकीकरण सफल नहीं होता, तो आज भारत का राजनीतिक स्वरूप काफी अलग हो सकता था। इसी असाधारण योगदान के कारण सरदार पटेल को ह्यभारत का लौह पुरुषह्ण कहा जाता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्त्व : भारत सरकार ने वर्ष 2014 में सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को मजबूत करना तथा पटेल के योगदान को याद करना है। इस अवसर पर देशभर में एकता दौड़, शपथ ग्रहण समारोह, संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस केवल एक महान नेता की जयंती मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन करने का दिन भी है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने दैनिक व्यवहार में एकता, सहिष्णुता और भाईचारे के मूल्यों को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं? क्या हम भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर पैदा होने वाली दूरियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं? विविधता में एकता ही भारत की पहचान : भारत की शक्ति उसकी भौगोलिक विशालता या आर्थिक क्षमता में ही नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकजुटता में भी निहित है। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से लेकर गुजरात के समुद्री तटों तक, कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी तक, अलग-अलग भाषाएं और परंपराएं होने के बावजूद भारतीयता की भावना हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। हालांकि, वर्तमान समय में समाज के सामने कई चुनौतियां भी हैं।

जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक तनाव, क्षेत्रीय असहिष्णुता, अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं। छोटी-छोटी बातों पर आपसी मतभेदों को दुश्मनी में बदल देना राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि देश की एकता केवल सरकारों या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि मतभेदों के बावजूद संवाद और सहयोग के माध्यम से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोगों के विचार एक जैसे हों, बल्कि इसका अर्थ है कि अलग-अलग विचार रखने के बावजूद हम संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध रहें।

युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण : भारत विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है। देश की युवा शक्ति यदि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, तो भारत विकास, विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। इसके लिए युवाओं में राष्ट्रप्रेम के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना आवश्यक है।

करवा चौथ: पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व

रमेश सर्राफ धमोरा

करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा बहना इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकरजी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्ध्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चाँदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान-प्रदान किया जाता है। जो आपसी प्रेमभाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएँ अपने सास-ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकरजी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया।



भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहां साल के सभी दिनों का महत्व है तथा साल का हर दिन पवित्र माना जाता है। करवा चौथ हिन्दुओं का प्रमुख त्योहार है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चन्द्रमा दर्शन के बाद सम्पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलायें करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। यह व्रत लगातार 12 अथवा 16 वर्ष तक हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवनभर इस व्रत को कर सकती हैं।

करवा चौथ का व्रत हर साल महिलाओं द्वारा अपने पतियों के लिए किया जाता है और यह न केवल त्यौहार है बल्कि पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व है। कहने को तो करवा चौथ का त्यौहार एक व्रत है लेकिन यह नारी शक्ति औ? उसकी क्षमताओं का सवश्रेष्ठ उदहारण हैं। क्योंकि नारी अपने दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती हैं तो फिर वह क्या नहीं कर सकती हैं। आज के नये जमाने में भी हमारे देश में महिलायें हर वर्ष करवा चौथ का व्रत पहले की तरह पूरी निष्ठा व भावना से मनाती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पत्नियाँ अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिए और कुछ भी खाए व्रत रखना आसान नहीं है लेकिन स्नेही पत्नियाँ अपने पति के प्रति पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। यह त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है।

शास्त्रों के अनुसार पति की दीघार्यु एवं अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचन्द्र गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिनभर उपवास रखकर रात में चन्द्रमा को अर्ध्य देने के उपरान्त भोजन का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं। लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्ध्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व पति के माता-पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी सासूजी को वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे न हों तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें।

कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध घी में आटे को सेंककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शक्कर की चासनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के अथवा तांबे के बने हुए अपनी सामर्थ्य अनुसार 10 अथवा 13 करवे रखें।

करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा बहना इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकरजी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्ध्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चाँदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान-प्रदान किया जाता है। जो आपसी प्रेमभाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएँ अपने सास-ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकरजी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया।

आधुनिक होते समाज में भी महिलायें अपने पति की दीघार्यु को लेकर सचेत रहती है। इसीलिये वो पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती है। पत्नी का अपने पति से कितने भी गिले-शिकवे रहे हों मगर करवा चौथ आते-आते सब भूलकर वो एकाग्र चित्त से अपने सुहाग की लम्बी उम्र की कामना से व्रत जरूर करती है। करवा चौथ शब्द करवा अर्थात मिट्टी का बर्तन और चौथ अर्थात चतुर्थी से मिलकर बना है। इस पर्व पर मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। सभी विवाहित महिलाएं पूरे वर्ष इस त्योहार की प्रतीक्षा करती हैं और इसकी सभी रस्मों को श्रद्धा के साथ निभाती हैं। किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं वे व्रत रखती हैं। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाल बांधकर ईश्वर का स्मरण कर स्थापित करें। पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। दिन में करवाचौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें।

इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीनकाल में एक ब्राह्मण था। उसके चार लडके एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी। तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही। कुछ खाया-पीया नहीं, पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से न रहा गया उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन चंद्रमा निकल आया है। पूजन कर भोजन ग्रहण करो।

बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुःखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थीं। उनसे उसका दुःख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुःख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्षभर की चौथ का व्रत नियमपूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथव्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीघार्यु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिन्दू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं।

कहते हैं इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल-कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। भारत देश में चौथमाता का सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। यहां के चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीमसिंह चौहान ने करवाया था।

शिक्षा समीक्षा बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर जोर

विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग नर्मदापुरम द्वारा विभागीय शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में केसला विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री हर्षित कौरव उपस्थित रहे। बैठक में विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा आगामी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण, विकासखंड में साइकिल वितरण, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा विद्यार्थियों के ओटीआर पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीयन एवं एमपीटास पोर्टल पर पंजीयन की स्थिति की जानकारी लेते हुए शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में त्रैमासिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर अभी से तैयारी प्रारंभ की जाए। विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाए। कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उन पर विशेष ध्यान देने और उनकी विषयवार कठिनाइयों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेईई एवं नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग से कक्षाओं का संचालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालयों में निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित समय-सीमा में पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के साथ विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई, अभ्यास एवं परीक्षा की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

शीतला माता मंदिर हादसा:

ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन के 40 अधिकारियों से होगी पूछताछ, बतानी होगी जिम्मेदारी व कारण

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



शीतला माता मंदिर हादसे को लेकर चल रही मजिस्ट्रियल जांच में लोगों से साक्ष्य और जानकारी आमंत्रित करने के सिलसिले के चलते दूसरे दिन मंगलवार को भी कोई नहीं पहुंचा। अब एक दिन बुधवार ही शेष बचा है। चार घंटे एडीएम न्यायालय में डाइस पर बैठे रहे। वहीं इस मजिस्ट्रियल जांच के चलते पुलिस और प्रशासन के 40 अधिकारियों को नोटिस जारी कर बुलाया जाएगा, उनसे इस मामले में उनकी जिम्मेदारी से लेकर हादसा कैसे हो गया यह कारण पूछा जाएगा। सभी के बयान दर्ज होने के बाद हादसे से जुड़ी हर कड़ी की पड़ताल होगी और इसके बाद जांच का निष्कर्ष निकलेगा। प्रशासन के अधिकारियों में पीडब्ल्यूडी से लेकर बिजली कंपनी सभी संबंधित विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वे पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जो इस मामले में सीएम की सख्ती के बाद निलंबित किए गए थे। बता दें कि शीतला माता मंदिर हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, चीनोर रोड से आ रहे ट्रक ने शीतला माता मंदिर गेट पर लोगों को रौंद दिया था। वहीं इस हादसे में 42 लोग घायल हो गए थे। कई लोगों को एयरलिफ्ट कर भोपाल इलाज के लिए भेजा गया। सीएम ने इस मामले में जांच के आदेश कर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। मजिस्ट्रियल जांच के तहत पुलिस से पूरा रिकॉर्ड लिया गया है जिसमें डयूटी आदेश से लेकर जो जो पुलिसवाले डयूटी पर थे उन सभी के नाम मंगवाए गए हैं। इसके अलावा शीतला माता मंदिर पर जो नवरात्र से पहले बैठक हुई थी उसमें शामिल प्रशासन के अधिकारी एसडीएम, सीएसपी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली कंपनी के इंजीनियर ,ट्रैफिक पुलिस सभी से जानकारी के लिए उन्हें बुलाया जाएगा।

इन पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई, होंगे बयान

सीएसपी रवि भदौरिया- पीएचक्यू अटैच- मंदिर झांसी रोड क्षेत्र में आता है, झांसी रोड थाना इनके सर्किल में आता था। निरीक्षक शक्ति सिंह यादव- निलंबित- मंदिर इनके थाना क्षेत्र में था इसलिए कार्रवाई। निरीक्षक गीतेश शर्मा- निलंबित- जहां से ओवरलोड ट्रक आया, उसका थोड़ा हिस्सा इनके क्षेत्र में था। रक्षित निरीक्षक अभिषेक रघुवंशी- निलंबित- झांसी रोड यातायात थाने के प्रभारी। वहीं डयूटी चार्ट में जिनके नाम उनमें निरीक्षक राघवेंद्र जादौन, प्र.आरक्षक सुशील द्विवेदी, आरक्षक किशन खन्ना, अनिल जैतपुरिया, पवन सेंगर निलंबित किए गए। इन सभी के एडीएम सीबी प्रसाद के समक्ष बयान दर्ज होंगे। तकनीकी जांच रिपोर्ट भी मांगी एडीएम सीबी प्रसाद की ओर से तकनीकी जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके लिए पीएचक्यू और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को पत्र लिखे गए हैं। दोनों के माध्यम से ट्रक की मैकेनिकल व तकनीकी जांच की गई है। ट्रक के ब्रेक प्रेशर फट जाने की आशंका फिलहाल सामने आई है।

बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे थे 38 लाख रुपये, दोषियों को मिली कैद

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



ग्वालियर जिला कोर्ट के षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने वरिष्ठ महिला नागरिक से 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 38 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में अंतिम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले से जुड़े तीन अभियुक्तों– हरीश चौधरी, अनिल नायक और ओमप्रकाश नायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 (चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना) और धारा 120-बी के तहत दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनने और जालसाजी से जुड़े कड़े आरोपों (धारा 420, 384, 467, 468, 471 और आईटी एक्ट की धारा 66-डी) में पर्याप्त सीधे सबूतों के अभाव के कारण न्यायालय ने उन्हें तकनीकी रूप से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, लेकिन धोखाधड़ी से प्राप्त धन का प्रबंधन करने और उसे छुपाने के अपराध में इन्हें सख्त सजा दी गई है। वहीं इस मामले में जांच में लापरवाही पर एसपी ग्वालियर को संबंधित अधिकारी की जांच कर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। जानकारी के अनुसार यह मामला अप्रैल 2024 का है। फरियादिया डॉ. सुजाता बापट निवासी गुलमोहर सिटी, ग्वालियर, को 9 अप्रैल 2024 को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को प्रसिद्ध कुरियर कंपनी 'डीएचएल' का कर्मचारी राजीव गुप्ता बताया। उसने महिला को डराते हुए कहा कि उनके नाम से लखनऊ से म्यांमार के लिए एक पार्सल बुक किया गया है, जिसमें एक लैपटॉप, पासपोर्ट और अवैध एमडीएमए ड्रग्स मिले हैं।

अधिनियम 1981 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग हटाने का आदेश

पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की याचिका पर जवाब देने के लिए मांगा एक महीने का समय

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह की याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिका में इसके स्थान पर नई राहत जोड़ने की अनुमति दी थी। अब मामले में राज्य सरकार को संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के साथ जवाब प्रस्तुत करना है, लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक माह का समय मांगा है। आठ सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की पीठ के समक्ष याचिका में संशोधन के आवेदन पर सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने बताया कि आवेदन में राहत संबंधी प्रार्थना को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता मूल राहत क्रमांक एक को हटाकर उसके स्थान पर आवेदन में उल्लिखित राहत क्रमांक 1-ए जोड़ना चाहता है। कोर्ट ने इस मौखिक अनुरोध को स्वीकार करते हुए संशोधन की अनुमति दे दी। इसके बाद संशोधित याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। नोटिस की तामील के लिए तीन कार्यदिवस के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने को कहा गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सीपी सिंह ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें एक महीने का समय देते हुए मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक आंकड़ों के साथ जवाब दाखिल करने को कहा, ताकि विवाद का प्रभावी निराकरण किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है। बता दें कि डॉ. गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में मांग की है कि 45 साल पुराने डकैती अधिनियम को अब अप्रासंगिक और असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए।

10 घंटे चली सुनवाई, दारूल कुरआन मदरसे के 22 बच्चे माता-पिता को सौंपे



एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

एजी ऑफिस स्थित दारूल कुरआन मदरसे में छापेमारी के बाद रेस्क्यू किए गए 26 बच्चों में 22 बच्चों को मंगलवार को बाल कल्याण समिति ने उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। चार बालक जो बाहरी राज्यों के हैं उनकी सोशल इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट यानी एसआइआर पूर्ण न हो पाने के कारण बुधवार को बच्चे दिए जाएंगे। सुबह दस बजे से गोविंदपुरी चौराहा स्थित कार्यालय में बाल कल्याण समिति के चार सदस्यों ने एसआइआर प्रक्रिया और काउंसिलिंग पूरी की और बच्चों को माता पिता के सामने सौंपा। रात तक चली प्रक्रिया में पूरे दिनभर बच्चों के परिवार का जमावड़ा लगा रहा और कई बार कार्यालय स्टाफ को बाहर भी निकालना पड़ गया। वहीं बच्चियों ने कार्उसिलिंग के दौरान भी बाल कल्याण समिति के सदस्यों के सामने मदरसे में मारपीट की बात को दोहराया, यानी बच्चियां अपने बयानों पर अडिग हैं। अब समिति की ओर से पुलिस को जांच प्रतिवेदन पहुंचना शेष है जिसके आधार पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।

पटाखे लेकर स्टेशन और ट्रेन में पहुंचे तो होगी सख्ती, दीपावली से पहले आरपीएफ हुई अलर्ट

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सतर्कता बढ़ा दी है। मंगलवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों के सामान की जांच कर ऐसे पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों पर नजर रखी गई। निरीक्षक के निर्देशन में चलाए गए अभियान में उप निरीक्षक रविन्द्र सिंह राजावत, सहायक उप निरीक्षक हीरेन्द्र मीना और आरक्षक दुजी राम मीणा शामिल रहे। टीम ने स्टेशन परिसर के साथ ट्रेनों में भी जांच की, ताकि यात्रा के दौरान आग लगने या किसी अन्य दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। त्योहार के दौरान पटाखों और अन्य ज्वलनशील सामग्री के परिवहन से खतरा बढ़ सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वेंडरों और कुलियों को भीकिया जागरूक अभियान के तहत स्टेशन के अधिकृत वेंडरों, कुलियों और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक भी की गई। उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों और ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने वालों पर नजर रखने की समझाइश दी गई। साथ ही, ऐसी कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल आरपीएफ को सूचित करने के लिए कहा गया।

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लगाई गई मूवेबल प्रदर्शनी

नशामुक्त समाज के लिए सामूहिक सहभागिता जरूरी-बीके प्रहलाद

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के यूथ विंग एवं मेडिकल विंग द्वारा आज कटोरा ताल रोड स्थित अम्मा महाराज की छतरी के बाहर नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, केंद्र प्रमुख बीके आदर्श दीदी के निर्देशन में मूवेबल प्रदर्शनी लगाई गई। आयोजित इस पहल का उद्देश्य जन-जन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ लोगों को स्वस्थ, खुशहाल एवं संस्कारवान जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। संस्थान के वरिष्ठ राजयोग ध्यान प्रशिक्षक बीके प्रहलाद भाई ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से नशे के कारण होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक नुकसान के बारे में बताया तथा लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया गया है। इसके साथ ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सकारात्मक सोच विकसित करने तथा आत्मबल और राजयोग ध्यान के माध्यम से नशे जैसी बुराइयों से मुक्त रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि परिवार की सुख-शांति और समाज पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए युवाओं की जागरूकता, दृढ़ संकल्प और सामूहिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। प्रदर्शनी का अवलोकन म.प्र. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉ प्रवीण अग्रवाल, एड. रविन्द्र नायक, सीए नमन मोदी, दाल बाजार से संतोष बंसल, राजेन्द्र सिंह, राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ प्रवीण मित्तल, डॉ मनीष चांदिल, पंकज, समाज सेवी दिनेश जैन, स्थानीय सांसद प्रतिनिधि सहित अनेकनेक लोगों ने किया।

गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल से निजी लैब की ओर भेजा जा रहा

सरकारी अस्पताल में प्राइवेट कंपनी को ठेके से मेडिकल जांचों का टोटा, मरीजों पर खर्च का बोझ

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



सरकारी अस्पताल में सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को जांच के नाम पर जेब ढीली करनी पड़ रही है। डॉक्टर बीमारी पकड़ने के लिए जरूरी जांच लिख रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की पैथोलाजी में वे जांचें उपलब्ध नहीं हैं। नतीजा, गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल से निजी लैब की ओर भेजा जा रहा है, जहां जांचों के लिए 1000 से 1500 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। मुरार जिला अस्पताल और हजीरा सिविल अस्पताल की स्थिति बताती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जांच की सुविधा का दावा मरीजों के लिए कितना अधूरा साबित हो रहा है। सबसे खराब स्थिति मुरार जिला अस्पताल की है। यहां 130 प्रकार की जांचों में से केवल 80 ही हो पा रही हैं। यानी करीब 50 तरह की जांचों के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट, सीआरपी, एलएफटी, पीटी -आइएनआर, एचबीएवनसी और आरए फैक्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण जांचें उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। डॉक्टर द्वारा जांच लिखे जाने के बाद भी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलती तो मरीज के सामने निजी लैब में पैसे खर्च करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता। हजीरा सिविल अस्पताल में भी हालात बेहतर नहीं हैं। यहां 112 तरह की जांचों में से 36 जांचें नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में नाममात्र शुल्क पर इलाज और जांच की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में पैथोलाजी सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी कुछ महीने पहले प्रदेश स्तर पर साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई थी। अनुबंध के तहत कंपनी को अस्पतालों में आधुनिक मशीनें स्थापित कर जांच सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करानी थीं। इसके बावजूद जरूरी सामग्री या संसाधन उपलब्ध नहीं होने से कई जांचें नहीं हो पा रही हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने एलएफटी जांच लिखी थी, लेकिन यहां जांच नहीं हो पाई। अब निजी लैब में जाकर जांच करानी पड़ेगी। अस्पताल में यह सुविधा कब शुरू होगी, पता नहीं। - धर्मेंद्र, मरीज डॉक्टर को दिखाने आई थी। उन्होंने चार से पांच जांचें लिखीं, लेकिन उनमें से एक जांच अस्पताल में नहीं हो सकी। अब उसे निजी लैब से कराना पड़ेगा। जांचों का टेंडर भोपाल स्तर से हुआ है। जांच सेवाओं को लेकर आ रही समस्याओं के संबंध में कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

डॉ. सीमा जायसवाल, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल मुरार

त्वचा का सौंदर्य निखारे चंदन का फेसपैक

सदियों से चंदन पूजा में इस्तेमाल होता आया है, साथ ही यह सौंदर्य के लिए भी उपयोगी माना जाता है। आखिर यूं ही तो चंदन सा बदन नहीं कहा जाता। सौंदर्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां भी बढ़-चढ़कर अपने उत्पादों में चंदन होने की दावा करती हैं। चंदन की लकड़ी का पाउडर त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है। चंदन में हीलिंग के गुण हैं, जो त्वचा को कई परेशानियों से बचाते हैं। गर्मियों में यह आपकी त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। चंदन की लकड़ी अथवा पाउडर से बना फेसपैक त्वचा को बेदाग निखार देता है।



दूध में मिलाकर पेस्ट बनाएं

अगर आप अपने चेहरे पर कांति लाना चाहते हैं तो चंदन और दूध का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाइए। चंदन के पाउडर में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर लगाइए। इस मिश्रण को 20 मिनट तक यूं ही लगा रहने दें और फिर पानी से अच्छी तरह चेहरा धो लें। आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार नजर आएगी। यह मिश्रण रूखी त्वचा वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है।

दाग धब्बों की छुट्टी

अगर आप अपने चेहरे से दाग-धब्बे हटाना चाहते हैं, तो इस हवाले से चंदन आपकी काफी मदद कर सकता है। चंदन के पाउडर में अच्छी तरह पिसे हुए बादाम और थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे, बाजुओं और टांगों पर रोजाना लगाया जा सकता है।

ऐसे बनाएं पेस्ट

चंदन कुदरती तौर पर पिंपल और एक्ने को भी आसानी से हटा देता है। चंदन और हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। जब यह पेस्ट अच्छी तरह सूख जाए तो इसे पानी से धोकर चेहरा पोंछ लें। इससे न केवल आपके चेहरे को पिंपल से छुटकारा मिलेगा बल्कि चेहरे पर नयी चमक भी आएगी। ऑयली त्वचा वालों के लिए यह पेस्ट काफी मददगार हो सकता है।

ऐसे बनाएं मास्क

चंदन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह जलन कम करने में सहायक होता है। चेहरे पर समय के साथ जमा धूल और मैल को हटाने में इसका फेस मास्क बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। चंदन पाउडर में थोड़ा गुलाब का पानी, हल्दी, मलाई और बेसन मिलाकर फेसपैक बनाइए। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर थोड़ी देर सूखने दें। थोड़ी देर बाद इस मास्क को हटा लें और चेहरा पानी से धो लें। आपकी त्वचा कोमल हो जाएगी।



फास्ट फूड्स को बनाएं हेल्दी, कंट्रोल रहेगा वजन

वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अनियमित जीवनशैली और फास्टफूड माना जाता है। दुनियाभर में लोग वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं। फास्ट फूड्स से वजन तेजी से बढ़ता है ये बात सच है। कुछ लोग फास्ट फूड के ऐसे दीवाने होते हैं कि वो इसे लाख चाहने के बाद भी नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अगर इसे बनाने के तरीके में थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाए तो फास्ट फूड को भी हेल्दी बनाया जा सकता है। अगर हम फास्टफूड को हेल्दी तरीके से बनाएं तो इससे हमारा वजन भी कंट्रोल रहेगा और हमें अपना मन भी नहीं मारना पड़ेगा।



पिज्जा

देखा जाए तो फास्ट फूड में ऐसी कई चीजें हैं, जिनसे हमें पोषण मिलता है। जैसे मोमोज में सब्जियां भरने के साथ ही इसे स्टीम से तैयार किया जाता है। इसमें मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेसमाल किया जा सकता है। इसी तरह चीज पिज्जा की जगह वेजिटेबल पिज्जा खाया जा सकता है। सैंडविच में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करके भी इसे हेल्दी व टेस्टी बना सकते हैं।

पास्ता

अगर आप पास्ता के शौकीन हैं तो बाहर से खाने की बजाय घर पर ही इसे बनाएं। पास्ता बनाते समय उसमें कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, ब्रोकली, खीरा, बंदगोभी या सलाद के पत्ते भी काटकर मिलाएं। यह पास्ता आपकी सेहत को कभी बिगड़ने नहीं देगा।

याददाश्त करे मजबूत

एक शोध में सामने आया है कि फास्ट फूड ब्रेन के लिए भी अच्छा है। रिसर्च टीम के मुताबिक, फ्राइड चीजों में पाए जाने वाले केमिकल्स दिमाग को चुस्त रखते हैं।

घर पर बनाएं ये हेयर मास्क, रुकेगा हेयरफॉल

बालों का गिरना एक समस्या की तरह है जो हर उम्र के लोगों में देखी जाती है। प्रदूषण, खानपान में पौष्टिक तत्वों की कमी, तनाव आदि हमारी दिनचर्या से जुड़ी आदतें ही बालों के गिरने का प्रमुख कारण है। गिरते बालों को रोकने से बचाने के लिए बाजार में कई तरह के उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी बालों की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन्हें गिरने से रोकने के लिए घर पर ही हेयर मास्क बनाएं और अपने गिरते बालों की समस्या को प्राकृतिक तरीके से रोकें।



अंडे की जर्दी

अंडा खाने और साबुत प्रयोग करने में भी बहुत फायदेमंद है, इसमें प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाता है। जबकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एक अंडे की जर्दी और दो चम्मच ग्रीन टी लीजिए, इसका पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों तक इसे अच्छे से लगाएं। 30 मिनट बाद बालों को धो लें, इस मास्क को सप्ताह में कम से कम तीन दिन प्रयोग करें।

केला

एक केला लें और एक अंडे की जर्दी निकाल लें, केले को अच्छी तरह से मसल कर अंडे की जर्दी में डालकर हेयर मास्क तैयार करें। इस मास्क को बालों पर लगाकर 30-40 मिनट के लिए छोड़ दें, हल्के गरम पानी से बालों को धो लें। कुछ ही दिनों में बालों का गिरना कम हो जाएगा।

शहद

एक चम्मच शहद, एक चम्मच रम, एक चम्मच कैस्टर तेल, अंडे की जर्दी, विटामिन ए और ई के कैप्सूल को लेकर अच्छे से मिक्स कर इसका मास्क तैयार कर लें। इस मास्क को बालों की जड़ों के साथ पूरे बाल में लगाएं और हल्के गरम तौलिये से बालों को लपेटकर एक घंटे के लिए छोड़ दें।

TODAY'S Dish

चावल कटलेट्स



सामग्री

पका चावल- 1 कप, उबला आलू- 1 बड़ा, मिक्स वेजिटेबल मे बींस, शिमला मिर्च, हरी प्याज, लाल और पीली शिमला मिर्च और गाजर - 1 कप बारीक कटा, प्याज- 1, अदरक- 2 चम्मच, हरी मिर्च- 1, लाल मिर्च पावडर- 1/2 चम्मच, धनिया पत्ती- 2 चम्मच, नमक- स्वादअनुसार, हल्दी पावडर- चुटकीभर, जीरा पावडर- 1/2 चम्मच, धनिया पावडर- 1/2 चम्मच, कार्न स्टार्च- 1 चम्मच, बेसन- 3 चम्मचए तेल- 3 चम्मच।

विधि

- सबसे पहले एक कटोरे में तेल छोड़कर सभी सामग्रियों को मिक्स करें।
- अब चावल को अच्छी तरह से मिश्रण में मिल जाना चाहिए।
- एक प्लेट लें थोड़ा सा मैदा लें। फिर मिश्रण की टिक्कियां बना कर मैदे में लपेट कर किनारे रखें।
- इसी तरह से ढेर सारी टिक्कियां बना लें।
- एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन टिक्कियों को तल लें।
- इन टिक्कियों को दोंनो ओर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें।
- फिर इन्हें एक पेपर नैप्किन पर निकालें और मच चाहे सॉस के साथ सर्व करें।

राशिफल

मेष

आज के दिन अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करें। सर्दी, कफ और बुखार के कारण स्वास्थ्य खराब रहेगा। स्वजनों से वियोग हो सकता है।

वृषभ

परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी। कुटुंब और मित्रों के साथ आनंद के पल बिताएँगे। आपकी आय और व्यापार- धंधे में वृद्धि होगी।

मिथुन

शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। नौकरी-व्यवसाय में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। व्यापारियों द्वारा काम की कदर होगी। पदोन्नति का योग है।

कर्क

आज के दिन आप धर्म ध्यान तथा देवदर्शन को अधिक समय देंगे। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का प्रसंग बनेगा। नौकरी पेशेवालों को लाभ होगा।

सिंह

आज का दिन थोड़ी सी परिकूलताओं वाला होगा। स्वास्थ्य के सम्बंध में आपको विशेष ध्यान रखने पड़ेंगे। बाहर खाने-पीने से बचें।

कन्या

आज आपका दिन अनुकूलता से परिपूर्ण रहेगा। जीवनसाथी के साथ आप निकटता के क्षण का आनंद उठा सकेंगे। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी।

तुला

घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। सुखदायक घटनाएं हो सकती है। कार्य में यश और सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

वृश्चिक

स्वास्थ्य के सम्बंध में थोड़ी शिकायत रहेगी। संतानों की समस्या आपको चिंतीत कर सकती है। मानहानि होने की संभावना है।

धनु

तन-मन में स्फूर्ति का अभाव हो सकता है। मन पर चिंता का भार रहेगा। पारिवारिक वातावरण कलुषित रहेगा। माता के साथ मनमुटाव होगा।

मकर

दैनिक कार्यों में अनुकूल परिस्थिति निर्मित होने पर राहत महसूस करेंगे। गृहस्थजीवन की समस्याएं हल होती हुई प्रतीत हो सकती है।

कुंभ

वाणी पर संयम रखेंगे तो आज बहुत सी समस्याओं में से बच जाएंगे। वाद-विवाद में गहरे न उतरें। स्वास्थ्य खराब रहेगा। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मीन

आज का दिन आनंद और उत्साह से परिपूर्ण रहेगा। घर में किसी मांगलिक प्रसंग का आयोजन होगा। नए कार्य का आरंभ करने के लिए शुभ दिन है।

स्वर्ण जयंती समारोह में रेनबो स्कूल स्टूडेंट्स आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू

प्रदेश में 5 लाख स्कूली बच्चों की आंखों की जांच करेगा शंकरा आई फाउंडेशन

एक सत बुलेटिन, इंदौर





शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया ने मध्यप्रदेश के तीन जिलों में पांच लाख स्कूली बच्चों की आंखों की जांच का संकल्प लिया है। बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित फाउंडेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में रेनबो स्कूल स्टूडेंट्स आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। दोनों ने नेत्र स्वास्थ्य और जरूरतमंदों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आंखें परमात्मा का अनमोल उपहार हैं। आंखों की रोशनी के बिना जीवन कठिन हो जाता है, इसलिए इनकी देखभाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है और ट्रॉमा सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने शंकरा आई फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पांच दशक से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करना गौरव की बात है। जरूरतमंदों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और दूसरों को भी सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को उपचार की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शंकरा आई फाउंडेशन द्वारा मध्यप्रदेश के तीन जिलों में पांच लाख स्कूली बच्चों की आंखों की जांच के संकल्प को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन को प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय और वंचित वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कार्यक्रम में शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के सेवा कार्यों पर आधारित लघु फिल्म दिखाई गई। इसमें बताया गया कि फाउंडेशन 10 राज्यों में 14 सुपर स्पेशियलिटी केंद्रों के माध्यम से नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है।

सिविल डिफेंस वालंटियर्स अब आपदा में जनता की रखवाली के लिए तैयार



एक सत बुलेटिन, भिण्ड

शहर में किसी भी संभावित आपदा एवं आपातकालीन परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नागरिकों और युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वालंटियर्स प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन हुआ। ग्वालियर रोड स्थित विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज परिसर में 22 से 28 अक्टूबर 2026 तक चले इस शिविर में कुल 100 वालंटियर्स ने उत्साह के साथ भाग लिया। आपदा प्रबंधन में मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत बनाने की इस पहल के तहत होमगार्ड्स के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने वालंटियर्स को आधुनिक आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, त्वरित प्राथमिक उपचार, तकनीकी रेस्क्यू ऑपरेशन तथा सीमित एवं उपलब्ध संसाधनों से प्रभावी बचाव की विशेष व्यावहारिक ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण के दौरान वालंटियर्स ने आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय, बचाव तकनीक और टीम वर्क को भी सीखा। समापन सत्र में अधिकारियों ने बढ़ाया हौसला समापन सत्र में अपर कलेक्टर भिण्ड श्री राजन बी नाडिया, होमगार्ड्स जिला सेनानी श्री आर.डी. सिंह एवं उनकी टीम विशेष रूप से उपस्थित रही। अतिथियों ने वालंटियर्स के जोश और अनुशासन की सराहना करते हुए उन्हें उत्साहित किया। वक्ताओं ने आपदा पूर्व तैयारी और कम्युनिटी रेस्पॉन्स के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वालंटियर्स आपदा के समय जनमानस को धैर्य रखने की प्रेरणा देंगे और जनता को यह भरोसा दिलाएंगे कि सहायता के लिए वे हमेशा उपलब्ध हैं।

युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए किया जाएगा प्रेरित



एक सत बुलेटिन, मुरैना

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पदमेश उपाध्याय एवं सिविल सर्जन डॉ. जी.एस. तोमर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को जिला चिकित्सालय मुरैना में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आर.एम.ओ. डॉ. डी.एस. यादव एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. सत्येंद्र कौरव की उपस्थिति में हुआ। अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना, इसके सेवन की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना तथा तंबाकू मुक्त वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही युवाओं को तंबाकू से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय का स्टाफ एवं उपचाररत मरीज उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्यगत नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विशेष रूप से युवाओं को इसकी लत से बचाने का संदेश दिया गया। जनसहभागिता एवं निरंतर जागरूकता के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण और तंबाकू मुक्त भविष्य की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं।जिले में युवाओं को तंबाकू के घातक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें नशा मुक्त स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0' का जिला स्तरीय औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता फैलाना है। अभियान के तहत जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों-अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश

मुरैना! कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पदमेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में कायाकल्प पहल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय मुरैना सहित जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में एक दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता एवं साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ वातावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। अभियान के तहत जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर एवं बाहर व्यापक साफ-सफाई कर सामूहिक श्रमदान किया गया। वरिष्ठ पार्षद श्री अरविंद भदौरिया, श्री दिनेश शर्मा एवं सिविल सर्जन डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर ने स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए श्रमदान किया और स्वास्थ्य संस्थाओं को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने का संदेश दिया। अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता एवं स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर कलेक्टर का सख्त एक्शन, 8 अधिकारियों पर अर्थदंड

अधिरोपित शास्ति राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराकर चालान की एक प्रति 03 कार्यदिवस के भीतर जिला कार्यालय में जमा करने निर्देश

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले 8 अधिकारियों पर एकमुश्त अर्थदंड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की है। विभागीय पोर्टल पर 27 एवं 28 अक्टूबर को की गई समीक्षा में समय-सीमा बाहर लंबित प्रकरण पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर निरंतर टीएल बैठकों एवं विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि कोई भी प्रकरण समय-सीमा बाहर लंबित न रहे। इस संबंध में पत्राचार कर कार्यशैली में सुधार हेतु सचेत भी किया जाता रहा है। इसके बावजूद पोर्टल समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने स्वमोतो संज्ञान लेते हुए अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ख) के तहत कार्रवाई की है। जिसमें जेएसओ फूड भिण्ड के समय सीमा से बाहर के 27 प्रकरण लंबित होने के



कारण एक हजार की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। बीआरसी गोहद के समय सीमा से बाहर के 08 प्रकरण लंबित होने के कारण एक हजार की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। सीएमओ नगर पालिका लहार के समय सीमा से बाहर के 05 प्रकरण लंबित होने के कारण एक हजार की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। सीएमओ नगर परिषद रौन के समय सीमा से बाहर के 02 प्रकरण लंबित होने के कारण पांच सौ की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। नायब तहसीलदार एण्डोरी के समय सीमा से बाहर के 01 प्रकरण लंबित होने के कारण 250 की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। सीईओ जनपद रौन के समय सीमा से बाहर के 06 प्रकरण लंबित होने के कारण एक हजार की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। नायब तहसीलदार देहगांव के समय सीमा से बाहर के 02 प्रकरण लंबित होने के कारण पांच सौ की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। तहसीलदार रौन के समय सीमा से बाहर के 01 प्रकरण लंबित होने के कारण 250 की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। सीईओ जनपद रौन के समय सीमा से बाहर के 06 प्रकरण लंबित होने के कारण एक हजार की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। नायब तहसीलदार देहगांव के समय सीमा से बाहर के 02 प्रकरण लंबित होने के कारण पांच सौ की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। तहसीलदार रौन के समय सीमा से बाहर के 01 प्रकरण लंबित होने के कारण 250 की एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति चेतावनी स्वरूप अधिरोपित की गई है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि मुख्य शीर्ष 0070, उपमुख्य शीर्ष 60, लघु शीर्ष 800, योजना 1066 लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराकर चालान की एक प्रति 03 कार्यदिवस के भीतर जिला कार्यालय में जमा कराएं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

युवा संगम/रोजगार मेले में 166 युवाओं ने कराया पंजीयन, 152 आवेदकों का प्राथमिक चयन

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन भिण्ड के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय भिण्ड, शासकीय संभागीय आईटीआई भिण्ड, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय एमजेएस महाविद्यालय भिण्ड में युवा संगम/रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मेले में कुल 166 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। उपस्थित विभिन्न कंपनियों द्वारा आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल एवं अनुभव के आधार पर साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया संपादित की गई, जिसमें 152 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। मेले में युवाओं को विभिन्न रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं शासन की रोजगारपरक योजनाओं के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि ऐसे रोजगार मेलों का उद्देश्य जिले के अधिकाधिक युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें स्वरोजगार एवं शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना है। भविष्य में भी युवाओं के हित में इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर आयोजित की जाएंगी।

शासकीय विद्यालय मुड़ियाखेड़ा में बाल अधिकार एवं महिला सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

मुरैना! शासकीय माध्यमिक विद्यालय मुड़ियाखेड़ा में बालक-बालिकाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल विवाह निषेध, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) तथा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को महिला एवं बालिका सुरक्षा के लिए उपलब्ध सहायता सेवाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपायों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक श्रीमती अपूर्वा चौधरी ने वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन 181 की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि संकट की स्थिति में महिलाओं एवं बालिकाओं को पुलिस सहायता, विधिक सहायता, आश्रय तथा आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने महिला एवं बालिका हित में संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध सहायता सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बाल अधिकारों तथा सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान के बारे में विस्तार से समझाया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने अथवा असुरक्षित महसूस करने पर बिना किसी भय या संकोच के अपने विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें तथा सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, श्रीमती रानू रावत सहित बालक-बालिकाएं उपस्थित रहे।

रबी सीजन एवं त्योहारी अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, समय पर ट्रांसफार्मर बदलने, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के निर्देश

प्रबंध संचालक अजय गुप्ता ने खजुराहो में सागर संभाग के तीन वृत्तों की समीक्षा की

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अजय गुप्ता ने आज छतरपुर जिले के खजुराहो में सागर संभाग के सागर, टीकमगढ़ एवं छतरपुर वृत्तों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विद्युत आपूर्ति की स्थिति, राजस्व संग्रहण, विद्युत चोरी पर नियंत्रण, प्रवर्तन गतिविधियों तथा विभिन्न विकास एवं विद्युतीकरण कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रबंध संचालक श्री गुप्ता ने कहा कि रबी सीजन एवं त्योहारी अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मैदानी अधिकारी सतत निगरानी रखें तथा विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में उन्हें निर्धारित समय-सीमा में बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्युत चोरी एवं अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सघन कार्रवाई करने तथा प्रवर्तन गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण



कंपनी के राजस्व की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए बकाया राशि की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजस्व संग्रहण से संबंधित गतिविधियों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। प्रबंध संचालक ने एसएसटीडी के कार्यों तथा वर्क प्लान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुविधा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे टोले-मजरों एवं बसाहटों का सर्वे कराया जाए, जहां पांच या पांच से अधिक घर स्थित हैं, ताकि पात्र बसाहटों में विद्युतीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए। विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता सेवाओं, राजस्व वसूली एवं विकास कार्यों में प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आम उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में कॉर्पोरेट कार्यालय से मुख्य महाप्रबंधक (प्रवर्तन) श्री पी.के. क्षत्रिय, मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्री एम.ए. कुरैशी, मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) श्री एस.के. निगम, मुख्य महाप्रबंधक ए. के.तिवारी, मुख्य अभियंता श्री एस.आर. यमदे, अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) श्री पी.के. अग्रवाल एवं महाप्रबंधक श्री नीरज कुचिया सहित सागर, टीकमगढ़ एवं छतरपुर वृत्तों के अधीक्षण अभियंता तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में सशक्त हुआ मध्यप्रदेश

परमार्थ ही सच्ची मानव सेवा : मुख्यमंत्री मोहन



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी संस्कृति में जीवात्मा की सेवा को ही सर्वोच्च धर्म माना गया है। सच्चे अर्थों में परमार्थ ही मानव मात्र की सेवा है। शंकरा आई फाउंडेशन ने पांच दशकों से निष्ठा और समर्पण के साथ जरूरतमंदों की नेत्र चिकित्सा कराकर ' नर सेवा ही नारायण सेवा' के संकल्प को साकार किया है। किसी व्यक्ति की आंखों की रौशनी लौटने से उसके जीवन में ही नहीं, पूरे परिवार में खुशियां लौट आती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से इंदौर में हुए शंकरा आई फाउंडेशन के स्वर्ण जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने फाउंडेशन के संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी पद्मश्री डॉ. आर.वी. रमानी, सह-संस्थापक डॉ. राधा रमानी सहित फाउंडेशन के सभी समर्पित चिकित्सकों और कर्मठ कर्मचारियों को 50 वर्षों की सफल सेवा यात्रा पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर विकास और जन कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। गरीब-जरूरतमंदों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिले। इस दिशा में योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। राज्य में हवाई संपर्क बेहतर हुआ है, जिसका लाभ राज्य में संचालित एयर एम्बुलेंस को भी मिल रहा है। एयर एम्बुलेंस संकट के समय गरीब-जरूरतमंदों को इलाज उपलब्ध कराने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, उद्योग एवं व्यापार, कृषि जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश सशक्त हुआ है। मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बने, यही हमारा संकल्प है। छोटी शुरुआत, सेवा का व्यापक विस्तार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मई 1977 में कांची के शंकराचार्यों से प्रेरणा लेकर डॉ. आर.वी. रमानी और डॉ. राधा रमानी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में जरूरतमंदों की सेवा के उद्देश्य से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की थी। आज यह पहल देश के दस राज्यों तक पहुंच चुकी है। फाउंडेशन के 14 सुपर स्पेशियलिटी नेत्र अस्पतालों में प्रतिदिन एक हजार से अधिक मरीजों को उपचार की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन में लगभग 80 प्रतिशत लोगों का नेत्र उपचार निःशुल्क किया जाता है, शेष 20 प्रतिशत लोग ही भुगतान कर उपचार प्राप्त करते हैं। ऐसी विशेष व्यवस्था यह तय करती है कि आर्थिक अभाव किसी जरूरतमंद के इलाज में बाधा न बने।

नेत्रदान के प्रति जागरूकता जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेत्रदान के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के जरिए इस पुनीत कार्य का संदेश जन-जन तक पहुंचाना होगा। स्कूलों, कॉलेजों, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती समारोह इस संस्थान को भविष्य के लिए नए लक्ष्य तय करने का भी समय है। मुख्यमंत्री ने कामना करते हुए कहा कि शंकरा आई फाउंडेशन अपने पूर्ण सेवाभाव के साथ आगे बढ़ते हुए अधिकाधिक जरूरतमंदों तक गुणवत्तापूर्ण नेत्र उपचार की सुविधा पहुंचाये। इससे पहले उप-मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी वर्चुअली जुड़कर शंकरा आई फाउंडेशन के स्वर्ण जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम में इंदौर के जनप्रतिनिधियों सहित नागरिकगण तथा आई सेंटर के सभी डॉक्टर्स एवं स्टॉफ उपस्थित थे।

पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के एमपीओएम पोर्टल का शुभारंभ



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में विभाग निरंतर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। 'विदेश छात्रवृत्ति पोर्टल' का शुभारंभ प्रदेश में डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी अंतर्निहित प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप वैश्विक मंच पर शैक्षणिक उन्नति के लिए निरंतर प्रोत्साहित करने में सहायक होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री गौर बुधवार को अपने निवास कार्यालय से विदेश छात्रवृत्ति एमपीओएम पोर्टल के शुभारंभ अवसर को संबोधित कर रही थी। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य के प्रतिभाशाली एवं पात्र विद्यार्थियों को विदेश स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा, शोध एवं कौशल विकास प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा छात्रवृत्ति योजना का लाभ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।

मध्यप्रदेश पुलिस में गुणवत्तापूर्ण एवं जनोन्मुखी पुलिसिंग को मिल रही नई पहचान

अक्टूबर माह में भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं अलीराजपुर की विभिन्न पुलिस इकाइयों को मिला ISO 9001: 2015 प्रमाणन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस थानों एवं कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अक्टूबर माह में प्रदेश के भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं अलीराजपुर जिलों की विभिन्न पुलिस इकाइयों को ढूस्ह 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि पुलिस इकाइयों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित करने, अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण, आधारभूत सुविधाओं में सुधार तथा आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएं



उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत थाना बागसेवनिया, थाना अशोका गार्डन, थाना कोलार, थाना खजूरी एवं एडिशनल डीसीपी कार्यालय जोन-3 को ढूस्ह 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। इन पुलिस इकाइयों में थानों के जीर्णोद्धार, पुराने अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण, पुलिसकर्मियों एवं आमजन के लिए बेहतर बैठने की व्यवस्था, परिसर के सौंदर्यीकरण तथा जनोन्मुखी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे पूर्व थाना मिसरोद, थाना रातीबड़ एवं महिला थाना भोपाल को भी ढूस्ह प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। थाना कोतवाली सिवनी एवं महिला थाना सिवनी को ढूस्ह 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इन पुलिस इकाइयों को अपराधों के प्रबंधन एवं नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनशांति, सुव्यवस्थित मालखाने, आधारभूत सुविधाओं तथा जनहितकारी पुलिस गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना कोतवाली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, अभिलेखों के संधारण एवं उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन भी किया गया।

प्रदेश में 17 संयुक्त बेंचों के माध्यम से 554 प्रकरणों की सुनवाई

संयुक्त बेंच में 51 प्रकरणों की सुनवाई, महिलाओं की समस्याओं के संवेदनशील समाधान पर जोर

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोग की संयुक्त बेंच में 51 प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव, सदस्य श्रीमती साधना स्थापक एवं सचिव श्री सुरेश तोमर ने आवेदकों और अनावेदकों के पक्ष सुने तथा संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया पर विचार किया। जनसुनवाई में महिला प्रताड़ना, दहेज संबंधी शिकायतों, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद, साइबर अपराध एवं संपत्ति संबंधी मामलों सहित विभिन्न शिकायतों पर सुनवाई की गई। इनमें महिला प्रताड़ना के 15, दहेज संबंधी 9, घरेलू अत्याचार के 9, कार्यस्थल पर प्रताड़ना के 3, पारिवारिक विवाद के 3, मारपीट और संपत्ति विवाद के 2-2 प्रकरण शामिल थे। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध, यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, विभागीय एवं अन्य प्रकृति के प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। जनसुनवाई के दौरान पारिवारिक विवाद एवं दहेज संबंधी शिकायत के एक प्रकरण में आवेदिका ने ससुराल पक्ष द्वारा आर्थिक मांग किए



जाने तथा घरेलू प्रताड़ना की शिकायत प्रस्तुत की। एक अन्य प्रकरण में विवाह का आश्वासन देकर कथित शोषण किए जाने संबंधी शिकायत पर सुनवाई की गई। आयोग ने संबंधित पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई पर विचार किया। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में मई 2026 में अध्यक्ष एवं सदस्यों के नवीन मनोनयन के समय कुल 31 हजार 825 शिकायतें लंबित थीं। आयोग द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 17 संयुक्त बेंच आयोजित की गईं। इन बेंचों में 554 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 143 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

पश्चिम मध्य रेल की 9वीं राज्य स्काउट्स एवं गाइड्स रैली का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक भोपाल में

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 9वीं राज्य रैली का आयोजन 1 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड, हबीबगंज रेलवे कॉलोनी, भोपाल में किया जाएगा। यह राज्य स्तरीय रैली पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख आयोजनों में से एक है। इसमें पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय सहित भोपाल, जबलपुर एवं कोटा मंडलों से लगभग 400 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स एवं यूनिट लीडर्स भाग लेंगे। इस आयोजन के माध्यम से प्रतिभागियों को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, टीमवर्क तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों को विकसित करने का अवसर मिलेगा। रैली के दौरान विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें प्रतिभागी अपनी प्रतिभा, कौशल, रचनात्मकता और संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस राज्य रैली का ग्रैंड कैंपफायर एवं समापन समारोह 4 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। समारोह में पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री दिलीप कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम मध्य रेल की इस राज्य रैली का उद्देश्य स्काउट्स एवं गाइड्स के माध्यम से युवाओं में सेवा, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना तथा संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका तीसरी बार हुई निरस्त

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मध्यप्रदेश में दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी एवं अवैध व्यापार के मामले में आरोपी मुकेश कुमार विश्वकर्मा की जमानत याचिका तीसरी बार माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, जबलपुर द्वारा निरस्त कर दी गई है। इस प्रकरण के सभी आरोपी 12 जून 2026 से जबलपुर जेल में निरुद्ध हैं। न्यायालय ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की विवेचना और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी को गंभीर एवं संवेदनशील अपराध माना। न्यायालय ने यह भी पाया कि वन्यजीव संरक्षण



अधिनियम की धारा 51(क) के अंतर्गत आरोपी के निर्दोष होने पर विश्वास करने का आधार नहीं है। इसके आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर ने 8 जून 2026 को कटनी जिले के ग्राम झिन्ना पिपरिया में खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड पर घेराबंदी कर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से लगभग 4.4 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क, एक मोटरसाइकिल और एक चार पहिया वाहन (सिरान सी-3) जब्त किया गया था। इस संबंध में वन अपराध दर्ज किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत संरक्षित है।

भोपाल मंडल होकर संचालित तीन जोड़ी ट्रेनों के सुपरफास्ट दर्जे में परिवर्तन, 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए ट्रेन नंबर

भोपाल। रेलवे द्वारा भोपाल मंडल होकर संचालित तीन जोड़ी ट्रेनों को गैर-सुपरफास्ट श्रेणी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेनों के नंबरों में परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तित ट्रेन नंबर 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। 1.गाड़ी संख्या 22177 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-बनारस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 11093 होगा। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 22178 बनारस-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 11094 होगा।2. गाड़ी संख्या 22129 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 11065 होगा। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 22130 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस तुलसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 11066 होगा।3. गाड़ी संख्या 12167 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 11067 होगा। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 12168 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नया ट्रेन नंबर 11068 होगा। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा की योजना बनाते समय परिवर्तित ट्रेन नंबरों का ध्यान रखें तथा यात्रा से संबंधित अद्यतन जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से प्राप्त करें।



जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता पर जोर, यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने की अपील

ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में वीडियो चलाने वालों की खैर नहीं, लगेगा भारी जुर्माना

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

रेल यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनना, रील देखना, वीडियो चलाना या स्पीकर मोड पर ऑडियो बजाना अन्य यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन सकता है। ट्रेन के कोचों, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालयों और अन्य रेलवे परिसरों में सभी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यात्रियों को मोबाइल फोन का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर नियंत्रित रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में नियमों के पालन का महत्व और बढ़ जाता है। रेलवे परिसर में यात्रियों की सुविधा प्रभावित करने वाले व्यवहार पर लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित परिस्थितियों में 1,000 तक का जुर्माना अथवा छह माह तक का कारावास अथवा दोनों लगाए जा सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल पर गाने, वीडियो, रील या अन्य ऑडियो सामग्री सुनते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें और मोबाइल का स्पीकर तेज आवाज में न चलाएं। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन का उपयोग



जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रा करते समय प्रत्येक यात्री को सहयात्रियों की सुविधा, आराम और निजता का ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल पर गाने सुनने, वीडियो देखने अथवा रील चलाने के लिए ईयरफोन का उपयोग करें तथा स्पीकर पर तेज आवाज में ऑडियो चलाने से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे नियमों का पालन करना सभी यात्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यात्रियों के छोटे-छोटे सहयोग से रेल यात्रा को अधिक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करते समय भी आवाज धीमी रखें, अनावश्यक तेज रिंगटोन से बचें और सहयात्रियों के आराम एवं निजता का सम्मान करें। विशेष रूप से रात के समय और वातानुकूलित कोचों में ध्वनि का स्तर नियंत्रित रखना जरूरी है, ताकि किसी यात्री की नींद या यात्रा में व्यवधान न हो। छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर सभी यात्री रेल यात्रा को अधिक सुखद और सुविधाजनक बना सकते हैं। रेलवे का संदेश स्पष्ट है– आपके मनोरंजन की सुविधा, दूसरों की परेशानी न बने। नियमों का पालन करें, ईयरफोन अपनाएं और सभी के लिए शांतिपूर्ण रेल यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग दें। ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सफर के दौरान मोबाइल के लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनने, रील देखने या ऊंची आवाज में बात करने वाले यात्रियों पर रेलवे प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सहयात्रियों की शांति में खलल डालने और असुविधा पहुँचाने की शिकायतों के बाद रेलवे ने सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है। प्लेटफॉर्म या प्रतीक्षालय (वेटिंग हॉल) में लाउडस्पीकर पर मनोरंजन करने वाले यात्रियों पर मौके पर ही 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482002 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादक: विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9893311784